बड़ा खुलासा: एल एंड टी कंपनी ने अपने...

पेज एक का शेष

आरटीआई में पूछा गया था कि एल एंड टी को बंद किए जाने के कारण क्या थे। कृपया इस संबंध में वह पत्र उपलब्ध कराया जाए, जिसके जरिए कारण बताकर अनुमति मांगी गई थी। श्रम विभाग ने जवाब दिया कि उनके पास ऐसी कोई सूचना या आवेदन नहीं है।

सरकार की भूमिका पर सवाल

आरटीआई में पूछा गया था कि क्या हरियाणा सरकार ने एल एंड टी प्रबंधन को फैक्ट्री बंद किए जाने की अनुमति दी, इसके जवाब में श्रम विभाग ने कहा कि ऐसी कोई सूचना उनके पास नहीं है। आरटीआई में एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया था कि क्या फैक्ट्री बंद किए जाने से पहले श्रम विभाग की एनफोर्समेंट एजेंसी ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया था, इससे भी श्रम विभाग ने इन्कार किया। उसने जवाब में कहा कि ऐसा निरीक्षण फील्ड स्टाफ करता है लेकिन मुख्यालय पर ऐसी सूचना नहीं है।

आरटीआई से यह साफ हो गया कि एल एंड टी को बंद करने की सारी कार्रवाई जुबानी जमाखर्च थी। फरीदाबाद में बैठा तत्कालीन डिप्टी लेबर कमिश्नर अजयपाल डूडी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से नियंत्रित किया जा रहा था। हालांकि ऐसी स्थिति में अधिकारी अपना दिमाग लगाते हैं लेकिन पैसा देखकर डूडी की आंखों पर पट्टी बंध गई थी। दस्तावेजों से साफ है कि अजयपाल डूडी ने जो भी कागजी कार्रवाई की, उसके संबंध में कोई भी सूचना मुख्यालय नहीं भेजी और न ही किसी तरह का कोई दस्तावेज ही चंडीगढ़ भेजा।

कर्मचारियों से एक अरब रुपये वसूले

एल एंड टी कंपनी ने देशभर में अपने 35000 कर्मचारियों के सामने 2003 में एक योजना पेश की कि हर कर्मचारी को सिर्फ एक बार एल एंड टी वेलफेयर फाउंडेशन में दो हजार रुपये अपने वेतन से देने होंगे। कंपनी इसके बदले एल एंड टी के इक्विटी शेयर देगी। इसके लिए कंपनी ने मुंबई मुख्यालय में भारतीय कामगार सेना से एक एग्रीमेंट किया। भारतीय कामगार सेना दरअसल शिवसेना का श्रमिक संगठन है। यह एग्रीमेंट एल एंड टी के फरीदाबाद स्विचगियर्स फैक्ट्री में लागू किया गया। यह सारे तथ्य दस्तावेजों में मौजूद हैं। जिसकी फोटोकॉपी मजदूर मोर्चा के पास उपलब्ध है।

संघर्ष जारी है : **जुझारू श्रमिक नेता उदय दीक्षित के साथ हरि कृष्ण (दाएं)**

कंपनी ने हर कर्मचारी के वेतन से दो हजार रुपये सिर्फ एक बार काटने की बजाय हर महीने दो हजार काटना शुरू कर दिया। ये पैसे 2003 से लेकर फरवरी 2008 तक काटे गए। यानी एक कर्मचारी के वेतन खाते से पांच साल में 32000 रुपये एल एंड टी वेलफेयर फाउंडेशन में डाले गए। दो साल के अंदर ही एल एंड टी के मालिक ने एक बोगस कंपनी एल एंड टी वेलफेयर कंपनी लिमिटेड कागजों में खड़ी कर दी और सारे पैसे इस कंपनी को इंटरनल ट्रांसफर कर दिए गए।

कर्मचारियों को चकमा देने के लिए इसके एवज में जो सर्टिफिकेट दिए गए उस पर वेलफेयर फाउंडेशन का जिक्र करते हुए कंपनी ने उसे कर्मचारी की तरफ से एल एंड टी वेलफेयर कंपनी लिमिटेड में ट्रांसफर करने की बात कही। कुछ ही कर्मचारी इस बात को समझ सके। लेकिन तब तक सारा पैसा ट्रांसफर हो चुका था। ये रकम करीब 1120000000 रुपये है। एल एंड टी कर्मचारियों के पास अब वेलफेयर कंपनी लिमिटेड के शेयर सर्टिफिकेट हैं जिनकी शेयर मार्केट में कोई कीमत नहीं है। लेकिन अगर एल एंड टी अपने शेयर सर्टिफिकेट देती तो कर्मचारी लाभ में रहते। बोगस कंपनी के शेयर कर्मचारियों के पास रद्दी कागज बनकर रह गए हैं। याद रहे कि फरीदाबाद का एल एंड टी प्लांट धोखाधड़ी करके फरवरी 2008 में बंद हो चुका था। इस तरह इस आर्थिक घोटाले के तार फरीदाबाद में बंद की गई कंपनी और उसकी जगह एल एंड टी इन्फोटेक खड़ी करने में सीधा संबंध जरूर है।

सरकारी जांच को मोदी सरकार ने दबाया

एल एंड टी की वेलफेयर फाउंडेशन को कंपनी लिमिटेड में बदलने की शिकायत वित्त मंत्रालय तक पहुंची तो उसने सारे मामले की जांच तत्कालीन वित्त सचिव राजीव टाकरू (आईएएस) को सौंपी। राजीव टाकरू ने जांच रिपोर्ट 28 मार्च 2014 को सौंप दी यानी केन्द्र में मोदी सरकार आने से करीब दो महीने पहले। यह रिपोर्ट कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के पश्चिमी क्षेत्र के रीजनल डायरेक्टर और रजिस्ट्रार आफ कंपनीज के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई। राजीव टाकरू की रिपोर्ट थोड़ा तकनीकी है। उसका लब्बोलुआब ये है कि कैसे एल एंड टी वेलफेयर कंपनी को किसी ट्रस्ट के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। यानी एल एंड टी ने वेलफेयर फाउंडेशन का जो ट्रस्ट बनाया, उससे वेलफेयर कंपनी लिमिटेड को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है।

जैसा कि ऊपर जिक्र किया जा चुका है कि ट्रस्ट के पैसे एल एंड टी वेलफेयर कंपनी लिमिटेड में अवैध तरीके से ट्रांसफर किए गए। टाकरू की रिपोर्ट में एक बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि ए. एम. नाइक इस ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा लाभार्थी है। टाकरू रिपोर्ट में इस शख्स को मिस्टर एएमएन लिखा गया है। इस पैसे का इधर-उधर निवेश किए जाने का जिक्र भी रिपोर्ट में है यानी पैसे को शेल कंपनियों में भी निवेश किया गया।

आप लोगों को याद होगा कि भाजपा-आरएसएस और मोदी ने जिस ब्लैक मनी की चर्चा करके सत्ता हथियाई थी, उस ब्लैकमनी के धंधे में एल एंड टी भी तो शामिल थी। लेकिन फर्जी ईमानदार मोदी सरकार ने आजतक एल एंड टी और इसके मालिक ए. एम. नाइक पर कोई कार्रवाई नहीं की। पूर्व वित्त सचिव राजीव टाकरू की जांच रिपोर्ट को हमेशा के लिए दबा दिया गया। अगर इस जांच रिपोर्ट पर मोदी सरकार ईमानदारी से पेश आती तो उसे नाइक को कांग्रेस द्वारा दिया गया पद्मभूषण पुरस्कार छीन लेना चाहिए था। लेकिन मोदी ने तो 2019 में इस भ्रष्ट गुजराती उद्योगपति पर पूरी कृपा बरसाते हुए पद्मविभूषण से नवाज दिया और एक बोर्ड की चेयरमैनी भी दे दी।

नई यूनियन क्या कर पाएगी

एल एंड टी कर्मचारियों की पुरानी यूनियन ने कर्मचारियों को कदम कदम पर धोखा दिया। इसलिए फरीदाबाद में कंपनी का अस्तित्व खत्म होने के बावजूद कुछ कर्मचारियों ने लॉयल एंड टारगेट लेबर एसोसिएशन बना ली है और इसी के जरिए उन्होंने अपनी लड़ाई छेड़ दी है। इसके अध्यक्ष मुंबई प्लांट से उदय दीक्षित हैं, जबकि फरीदाबाद से हरि कृष्ण इसके महासचिव हैं। उदय दीक्षित और हरि कृष्ण से मजदूर मोर्चा संवाददाता ने बात की। उन्होंने पांच साल तक कर्मचारियों का पैसा कंपनी द्वारा हड़पने के तथ्य की पुष्टि की। उन्होंने यह भी माना कि एल एंड टी की पुरानी यूनियन के सारे नेताओं को ए. एम. नाइक ने ख़रीद लिया था।

दीक्षित ने कहा कि हमने मुंबई में शिवसेना के नेताओं से संपर्क किया था। नेता कम पत्रकार संजय राउत से बात की लेकिन एल एंड टी का मालिक बहुत पहुंच वाला है। हर पार्टी में उसकी पहुंच है। इसलिए कोई भी एल एंड टी के आर्थिक घोटाले और मजदूर विरोधी नीतियों पर बात नहीं करना चाहता। हमने कोशिश की कि कोई भी विपक्षी दल संसद में फरीदाबाद और मुंबई प्लांट के कर्मचारियों की आवाज उठाए लेकिन कोई भी पार्टी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। दीक्षित ने कहा कि यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि जिस कांग्रेस ने डॉ. मनमोहन सिंह के समय में ए. एम. नाइक को पद्मभूषण दिया था, उसी भ्रष्ट शख्स को भाजपा और मोदी सरकार ने न सिर्फ पद्मविभूषण दिया बल्कि अब उसे स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन तक बना दिया।

करनाल नगर निगम को मिली मशीन

करनाल, (ममो): शहर की सीवर लाइनें अब चोक नहीं रहेंगी। इसके लिए नगर निगम को स्मार्ट सिटी की ओर से एक नई सुपर सकर मशीन मिल गई है। गुरूवार से ही मशीन ने हांसी रोड पर जाकर अपना काम शुरू कर दिया है, जो सीवर लाइनों के मैन होल साफ करेगी।

नगर निगम आयुक्त विक्रम ने हांसी रोड पर दौरा कर नई मशीन का काम देखने के बाद बताया कि नई मशीन कुछ दिन इसी रोड पर रहेगी और पुरानी मशीन कुंजपुरा रोड की सीवर लाइनों के मैन होल साफ करेगी। इसके लिए 10 दिन का समय दिया गया है।

गतांक की चीर-फ़ाड़

सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार के प्रति वफ़ादारी

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 17-23 जनवरी 2021 के अंक में समसामयिक ज्वलंत मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार व लेख प्रकाशि हुए हैं। मोदी सरकार के तीन विवादित कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर चल रहे देशव्यापी किसान आन्दोलन के संगठनों के नेताओं और केन्द्र सरकार के बीच कई दौर की बेनतीजा बात-चीत संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को कड़ी फ़टकार तथा कृषि कानूनों के अमल पर रोक तो लगा दी, लेकिन किसानों और सरकार के बीच गतिरोध को खत्म करने तथा इन कृषि कानूनों की समीक्षा करने के लिये अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी, भूपिन्दर सिंह मान तथा अनिल धनवत की चार सदस्यी एक कमेटी गठित कर दी। ध्यान रहे कि ये चारों सदस्य इन कृषि कानूनों व मोदी सरकार के इस कदम के कट्टर समर्थक रहे हैं, जिसको 'कमेटी में गेट्स फ़ाउंडेशन का बोलबाला' में बेनकाब किया गया है।

गौरतलब है कि कमेटी के सदस्यों की निष्पक्षता पर किसानों और विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने पर कमेटी के सदस्य व भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिन्दर सिंह मान ने कहा कि उन्होंने किसानों के जज्बात और हालात व उनकी भावनाओं के मद्देनज़र कमेटी से अलग होने का निर्णय किया है तथा तीनों ही कृषि कानून किसानों के हक में नहीं है। स्पष्ट है कि कमेटी के सभी सदस्य किसानों की बजाए कॉरपोरेट घरानों और बहुराष्ट्रीय खाद्य कंपनियों के हितों के पैरोकार हैं।

सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार के प्रति वफ़ादारी और मोदी सरकार व कृषि कानूनों के समर्थकों की कमेटी गठित करने पर 'कविता/किसान कमेटी' और 'हरियाणवी परिहास' के जरिए व्यंग्यात्मक शैली में उपयुक्त तंज कसा गया है।

किसान नेताओं ने 19 जनवरी को दिल्ली पुलिस से मिलकर दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर 26 जनवरी को शांतिपूर्वक किसान ट्रैक्टर परेड करने की इजाजत के लिये कहा तो पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बता कर टाल दिया।

स्मरण रहे कि आरएसएस व भाजपा को सत्ता प्राप्ति में साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण का सदैव अहम योगदान रहा है।

आरएसएस व भाजपा गाय के दुध, गोमूत्र, गोबर आदि की उपयोगिता के बारे में प्रचार अभियान चलाए हुए हैं। 'खबर मरम्मत-और अब गोबर पेंट' में भाजपा नेताओं द्वारा गोबर पेंट के नॉन टॉक्सिक तथा गोमूत्र से कैंसर और कोरोना ठीक होने व गोबर से न्यूक्लियर हमले से बचने के काल्पनिक दावों का विवेचन किया गया है।

जबकि पश्चिमी बंगाल में गोमूत्र के सेवन से कोरोना वायरस से बचने तथा पहले से संक्रमित लोगों के ठीक होने के भाजपा कार्यकर्ताओं के दावे पर कुछ नागरिक स्वयंसेवी गोमूत्र सेवन के बाद बीमार पड़ गए थे। पीड़ित की शिकायत पर भाजपा कार्यकर्ता को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया था। इससे भाजपा के दावे की कलई खुल जाती है।

पीयूष हाइट्स सोसाइटी की आरडब्ल्यूए द्वारा पुलिस, बिजली विभाग तथा रजिस्ट्रार सोसाइटी की मिलीभगत से फ्लैट मालिकों से की जा रही लूट। बदतमीजी तथा मारपीट की वारदातों का 'आरडब्ल्यूए का गुंडाराज, महिलाओं से छेड़खानी, पुलिस तमाशबीन-पीयूष हाइट्स:बिजली मीटर के नाम पर वसूली, विरोध करने वालों की पिटाई' में भंडा-फ़ोड़ किया गया है।

विचारणीय है कि आरडब्ल्यूए को चलाने वाले अध्यक्ष समेत अन्य व्यक्ति वहां की सोसाइटी के रेजिडेंट्स न होते हुए भी आरडब्ल्यूए के प्रबंधक बने हुए हैं। इस अनियमितता के प्रति रजिस्ट्रार सोसाइटी ने आंखें बंद कर रखी है। दरअसल आरडब्ल्यूए की गुंडागर्दी के लिये रेजिडेंट्स की आपसी एकजुटता की कमी भी एक हद तक जिम्मेवार है।

मोदी सरकार ने अपने समर्थक मीडिया और संघ परिवार तथा राजनीतिक-सामाजिक प्रचार तंत्र के जरिए किसान नेताओं को बदनाम करने व उकसाने की मुहिम में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन किसान परिपक्वता का परिचय देते हुए अनुशासित व शान्तिपूर्ण बने रहकर 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड के लिये दिल्ली मार्च की तैयारी में जुटे हुए हैं, जिसका जब दिल्ली में किसान और पुलिस आमने-सामने होंगे' तथा 'राजेवाल का किसानों को खुला पत्र, कहा,-किसी भी कीमत पर हिंसक नहीं होने देना है आन्दोलन' में खुलासा किया गया है।

चाइनीज सुई लगवा लो

जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी वहां आठ महीने में वैक्सीन बन गयी।

-रिपब्लिक भारत

सुई तो अब भी नहीं बनी। वैक्सीन लगवाने के लिए भी चाईना से मंगाई गई है।

किसान आन्दोलन के लंबा खिंचने से बढती परेशानी व संकट में घिरी मोदी सरकार के साथ-साथ आरएसएस व भाजपा अपने हिंदू वोट बैंक को बिखरने से बचाने तथा आगामी चुनावों को जीतने के लिये राम मंदिर के लिये चंदा जुटाने, लव जिहाद व अन्य हथकंडों द्वारा साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण व धार्मिक उन्माद फ़ैलाने के लिये जुटी हुई है, जिसका 'किसानों की नहीं, हिंदू वोट बैंक की है चिन्ता' में पर्दाफाश किया गया है।